वृहत आर्थिक रूपरेखा विवरण 2019-20

अर्थव्यवस्था का सिंहावलोकन

वास्तविक जीडीपी वृद्धि में 2017-18 की तुलना में 40 आधार बिन्दुओं की गिरावट आने के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था वृहत आर्थिक स्थिरता के साथ सबसे तेज विकास करने वाली बनी हुई है। 2018-19 में नियत निवेश दर में तेजी आई थी। राजकोषीय स्थिति सुखद बनी रही और समेकन की प्रक्रिया लोक ऋण के ऊंचे स्तर को कम करने हेतु जारी रही। उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति द्वारा निर्धारित लक्षित सीमा के भीतर थी। चालू खाता घाटा 2017-18 में जीडीपी के 1.9 प्रतिशत से बढ़कर अप्रैल-दिसम्बर, 2018 में 2.4 प्रतिशत हो गया। भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्विक विश्वसनीयता बढ़ी है जैसा कि व्यवसाय करना आसान बनाने और सकल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतर्वाह में सुधार जैसे संसूचकों से देखा जा सकता है। विश्व बैंक की व्यवसाय करना आसान बनाने संबंधी रिपोर्ट 2019 के अनुसार, 2018 में भारत का स्थान 23 अंक सुधर कर 77वां हो गया है।

भारत विश्व में महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है और मध्यावधिक वृद्धि की संभावना मुख्य रूप से पिछले कुछ वर्षों में शुरू किए गए महत्वपूर्ण संरचनात्मक सुधारों की पृष्ठभूमि में उज्ज्वल है।

सरकार द्वारा विभिन्न उपाय किए गए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ 2018-19 के लिए कृषि फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि, कपड़ा और हस्तशिल्प के विकास हेतु नीतिगत पहलों, वृद्धि के लिए आउटरीच कार्यक्रम, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का विस्तार और सुविधा, स्टार्टअप इंण्डिया के लिए प्रोत्साहन, किफायती आवासों हेतु कम प्रभावी माल और वस्तु कर दर, पनबिजली क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के उपाय, एथेनाल उत्पादन की क्षमता बढ़ाने के द्वारा गन्ना क्षेत्र और गन्ना किसानों को सहायता एवं उन्नत भारत कार्यक्रम शामिल हैं। इसके अलावा विनिर्माण, रोजगार सृजन, वित्तीय समावेशन बढ़ाने के लिए, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण जैसी स्कीमों के जरिए व्यवसाय करना आसान बनाने में सुधार के अनेक कदम उठाए गए हैं। देश में अवसंरचना सुधार और विकास पर लगातार ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है।

आर्थिक वृद्धि

वार्षिक राष्ट्रीय आय के अनंतिम अनुमानों के अनुसार, वास्तविक आर्थिक वृद्धि 2017-18 में 7.2 प्रतिशत की तुलना में 2018-19 में 6.8 प्रतिशत हुई थी। जीडीपी की वृद्धि की गति में इस गिरावट का मुख्य कारण कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्र, और सेवा क्षेत्र (वित्तीय, स्थावर संपदा और व्यावसायिक सेवाओं को छोड़कर) में कम वृद्धि है। स्थिर मूल्यों (2011-12) आधार मूल्यों पर सकल मूल्य वर्धित वृद्धि 2017-18 में हासिल की गई 6.9 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 2018-19 में 6.6 प्रतिशत थी। कृषि, उद्योग और सेवाओं में वृद्धि 2017-18 में क्रमशः 5.0 प्रतिशत, 5.9 प्रतिशत और 8.1 प्रतिशत की तुलना में 2018-19 में क्रमशः 2.9 प्रतिशत, 6.9 प्रतिशत और 7.5 प्रतिशत हुई थी। मांग पक्ष से निजी अंतिम उपभोग व्यय वृद्धि का महत्वपूर्ण कारण है और अर्थव्यवस्था के जीडीपी में इसकी प्रमुख हिस्सेदारी (60 प्रतिशत के आसपास है), इसकी वृद्धि दर अधिकांशतः समग्र जीडीपी वृद्धि दर से अधिक है। स्थिर मूल्य पर नियत निवेश की वृद्धि दर 2017-18 में 9.3 प्रतिशत से बढ़कर 2018-19 में 10.0 प्रतिशत हो गई। वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात और आयात में 2017-18 में क्रमशः 4.7 प्रतिशत और 17.6 प्रतिशत की तुलना में 2018-19 में (स्थिर मूल्यों पर) क्रमशः 12.5 प्रतिशत और 15.4 प्रतिशत वृद्धि हुई।

मूल्य

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (समिश्र) पर आधारित मुद्रास्फीति 2017-18 में 3.6 प्रतिशत से गिरगर 2018-19 में 3.4 प्रतिशत पर आ गई। मई, 2019 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति 3 प्रतिशत थी। खाद्य मुद्रास्फीति के संदर्भ में औसत उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक 2015-16 में 4.9 प्रतिशत और 2016-17 में 4.2 प्रतिशत, 2017-18 में 1.8 प्रतिशत से घटकर 0.1 प्रतिशत पर आ गई। मई, 2019 में उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति 1.8 प्रतिशत थी।

थोक मूल्य सूचकांक के संदर्भ में मापी जाने वाली औसत मुद्रास्फीति 2018-19 में 4.3 प्रतिशत थी जबकि 2017-18 में यह 3.0 प्रतिशत थी। मई, 2019 में थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति 2.5 प्रतिशत थी। थोक मूल्य सूचकांक खाद्य मुद्रास्फिीति 2017-18 में 1.9 प्रतिशत से गिरकर 2018-19 में 0.6 प्रतिशत पर आ गई। मई, 2019 में थोक मूल्य सूचकांक खाद्य मुद्रास्फिीति 5.1 प्रतिशत थी।

केन्द्र सरकार के वित्त साधन

2017-18 के लिए राजकोषीय घाटा लक्ष्य हेतु जीडीपी का 3.2 प्रतिशत की बजट व्यवस्था की गई थी। परन्तु, इसमें 0.3 प्रतिशत का उछाल आया और राजकोषीय घाटा जीडीपी का 3.5 प्रतिशत पर आ गया था। राजकोषीय और राजस्व घाटे के लिए 2018-19 में उच्च स्तर की बजट व्यवस्था की गई थी अर्थात क्रमशः ₹6,24,276 करोड़ (जीडीपी का 3.3 प्रतिशत) और ₹4,16,034 करोड़ (जीडीपी का 2.2

प्रतिशत)। अनंतिम वास्तविक आंकड़ों के अनुसार, 2018-19 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 3.4 प्रतिशत और राजस्व घाटा जीडीपी का 2.3 प्रतिशत था।

वर्ष 2018-19 के लिए बजट अनुमान (ब.अ.) में 2017-18 (सं.अ.) की तुलना में सकल कर राजस्व में 16.7 प्रतिशत वृद्धि होने का अनुमान था। 2018-19 ब.अ. में कुल व्यय 2017-18 के सं.अ. की तुलना में 10.1 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान था।

महालेखा नियंत्रक द्वारा जारी 2018-19 के लिए केन्द्रीय सरकार के वित्त साधन संबंधी अनंतिम वास्तविक आंकड़ों के अनुसार, सकल कर राजस्व 2017-18 की तुलना में 8.4 प्रतिशत बढ़ा और यह 2018-19 ब.अ. का 91.6 प्रतिशत था। कर भिन्न राजस्व में 2017-18 के वास्तविक आंकड़ों की तुलना में 27.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। मुख्य सब्सिडियां, 2017-18 के वस्तविक आंकड़ों की तुलना में 2018-19 के दौरान 3.1 प्रतिशत (अ.वा.) बढ़ी। खाद्य सब्सिडी में ₹1,622 करोड़ की वृद्धि हुई, पेट्रोलियम सब्सिडी में ₹104 करोड़ की वृद्धि हुई जबकि 2017-18 के वास्तविक आंकड़ों की तुलना में 2018-19 के दौरान उर्वरक सब्सिडी में ₹4157 करोड़ ` की वृद्धि हुई।

2018-19 में राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटा क्रमशः ब.अ. का 103 प्रतिशत और ब.अ. का 107 प्रतिशत था। 2018-19 में संशोधित अनुमानों में राजकोषीय और राजस्व घाटे को क्रमशः जीडीपी के 3.3 प्रतिशत और 2.3 प्रतिशत रखा गया।

मौद्रिक प्रबंधन और वित्तीय मध्यस्थता

मौद्रिक नीति समिति ने अपनी पहले द्विमासिक विवरण में मौद्रिक नीति की स्थिति बदलकर अंशांकित कठोर से सामान्य बनाने का निर्णय लिया और अप्रैल, 2019 में नीति रेपो दर 25 आधार बिन्दु घटाकर 6.0 प्रतिशत कर दिया। जून, 2019-20 के लिए दूसरे द्विमासिक नीति विवरण में नीति दर और 25 आधार बिन्दु घटा दिया गया, इसके परिणामस्वरूप नीति रेपो दर 5.75 प्रतिशत हो गई। मौद्रिक नीति की स्थिति सामान्य से सुनम्य हो गई थी।

2018-19 के दौरान, कुल मौद्रिक वृद्धि दर विमुद्रीकरण के चलते 2016-17 में अभूतपूर्व चाल के बाद और दुबारा 2017-18 में पुनः मुद्रीकरण की प्रक्रिया के कारण अपनी दीर्घावधिक प्रवृत्ति में वापस आई। आरक्षित मुद्रा (एमओ) में 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार पिछले वर्ष की तुलना में 14.5 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई। आरक्षित मुद्रा में विस्तार का स्रोत मुख्य रूप से प्रचलन में रहने वाली मुद्रा थी।

स्थूल मुद्रा (एम 3) की वृद्धि में 2009 से गिरावट की प्रवृत्ति रही। तथापि, 2018-19 में कुल जमा राशियों द्वारा संचलित होकर स्थूल मुद्रा की वृद्धि में मामूली सुधार आया। घटक पक्ष से वर्ष के दौरान स्थूल मुद्रा में वृद्धि का आधार विस्तृत था, इसमें मुद्रा और जमा राशि दोनों से सहायता मिली। स्रोतों में, वाणिज्यिक क्षेत्र को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ऋण दिए जाने के कारण वर्ष के दौरान स्थूल मुद्रा में वृद्धि हुई। 2018-19 के दौरान मांग और सावधि जमा राशि की वृद्धि बढ़ी। कुल जमा राशि की वृद्धि 2017-18 के अंत में 5.8 प्रतिशत की तुलना में 2018-19 के अंत में 9.6 प्रतिशत हुई थी।

विदेशी क्षेत्र

व्यापार घाटा पिछले वर्ष में 162.1 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर 2018-19 के दौरान 183.5 बिलियन अमरीकी डालर पर आ गया।

भारत के पण्य वस्तु निर्यात का मूल्य (सीमा शुल्क आधार पर) पिछले वर्ष 303.5 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर 2018-19 में 329.5 बिलियन अमरीकी डालर पर 8.6 प्रतिशत हो गया। आयातों में भी पिछले वर्ष में 465.6 बिलियन अमरीकी डालर से 2018-19 में 10.2 प्रतिशत पर 513.1 बिलियन अमरीकी डालर की बढ़ोतरी हुई। पेट्रोलियम, तेल और स्नेहकों के आयात में पिछले वर्ष 108.7 बिलियन अमरीकी डालर से 2018-19 में 29.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई और 140.9 बिलियन अमरीकी डालर हो गया, यह मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि के कारण हुआ। गैर-पेट्रोलियम, तेल और स्नेहकों के आयात में 2018-19 में 4.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह पिछले वर्ष में 356.9 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर 372.2 बिलियन अमरीकी डालर हो गया। पण्य वस्तु निर्यात और आयात दोनों में वृद्धि 2017-18 की तुलना में 2018-19 में नरम रही, तथापि आयात वृद्धि, निर्यात वृद्धि की तुलना में अधिक तेजी से गिरी।

2018-19 की तीसरी तिमाही की पहली तीन तिमाहियों के लिए उपलब्ध भुगतान शेष के आंकड़ों के आधार पर भुगतान शेष के आधार पर व्यापार घाटा अप्रैल-दिसम्बर, 2017 में 118.4 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर अप्रैल-दिसम्बर, 2018 में 145.3 बिलियन अमरीकी डालर हो गया। निवल अदृश्य अधिशेष, निवल सेवा और निवल निजी अंतरणों में देखी गई वृद्धि से अप्रैल-दिसम्बर, 2017 में 82.8 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर अप्रैल-दिसम्बर, 2018 में 93.4 बिलियन अमरीकी डालर हो गया। निवल सेवा प्राप्तियों में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में अप्रैल-दिसम्बर, 2018 में 0.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई ।

अप्रैल-दिसम्बर, 2018-19 के दौरान निवल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, अप्रैल-दिसम्बर, 2017-18 में 23.9 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में 24.8 बिलियन अमरीकी डालर था। निवल पोर्टफोलियो के मामले में, पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 19.8 बिलियन अमरीकी डालर के निवल अंतर्वाह की तुलना में अप्रैल-दिसम्बर, 2018-19 में 10.1 बिलियन अमरीकी डालर का बहिर्वाह हुआ था।

भारत का चालू खाता घाटा अप्रैल-दिसम्बर 2017 में 35.7 बिलियन अमरीकी डालर (जीडीपी का 1.8 प्रतिशत) से बढ़कर अप्रैल-दिसम्बर, 2018 में 51.9 बिलियन अमरीकी डालर (जीडीपी का 2.6 प्रतिशत) पर आ गया। भुगतान शेष के आधार पर, अप्रैल-दिसम्बर, 2018 में भारत की विदेशी मुद्रा भण्डार में 17.5 बिलियन अमरीकी डालर की निवल कमी आई, जिसमें 29.0 बिलियन अमरीकी डालर पर मूल्य निर्धारण परिवर्तन शामिल है। दिसम्बर अंत 2018 में विदेशी मुद्रा भण्डार 395.6 बिलियन अमरीकी डालर था। जबकि व्यापार घाटा अप्रैल-दिसम्बर, 2017 की तुलना में अप्रैल-दिसम्बर, 2018 में बढ़ गया। चालू खाता घाटे का वित्तपोषण करने के लिए अदृश्य शेष और बैंकिंग पूंजी में सुधार पर्याप्त नहीं था, जिसके परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा भण्डार में अप्रैल-दिसम्बर, 2018 में कमी आई।

वर्ष 2018-19 में रुपये की औसत मासिक विनिमय दर (भारतीय रिजर्व बैंक की संदर्भ दर) प्रति अमरीकी डालर ₹68.62 थी। 2017-18 में प्रति अमरीकी डालर ₹65.04 से 5.2 प्रतिशत मूल्यह्रास हुआ।

बैंकिंग क्षेत्र

वर्ष 2018-19 में बैंकिंग क्षेत्र (घरेलू प्रचालन), विशेषकर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रदर्शन में सुधार हुआ। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की सकल अनर्जक अग्रिमों (जीएनपीए) का अनुपात मार्च, 2018 और दिसम्बर, 2018 के बीच 11.5 प्रतिशत से घटकर 10.1 प्रतिशत पर आ गया, और इसी प्रकार उनके पुनर्संरचित मानक अग्रिमों (आरएसए) का अनुपात 0.7 प्रतिशत से घटकर 0.4 प्रतिशत पर आ गया। इसी अवधि के दौरान भारग्रस्त अग्रिमों (एसए) का अनुपात 12.1 प्रतिशत से घटकर 10.5 प्रतिशत पर आ गया। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का जीएनपीए अनुपात मार्च, 2018 और दिसम्बर, 2018 के बीच 15.5 प्रतिशत से घटकर 13.9 प्रतिशत पर आ गया। इसी अवधि के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का भारग्रस्त अग्रिमों का अनुपात 16.3 प्रतिशत से घटकर 14.4 प्रतिशत पर आ गया।

खाद्य-भिन्न बैंक ऋण (एनएफसी) में वृद्धि जो पिछले कुछ वर्षों में धीमी रही, 2018-19 में कुछ सुधार हुआ। 2018-19 में औसत एनएफसी वृद्धि 2017-18 में 7.7 प्रतिशत की तुलना में बेहतर होकर 11.2 प्रतिशत हो गई। बड़े उद्योगों और सेवा सेगमेंट को बैंक ऋण 2018-19 में एनएफसी की समग्र वृद्धि के मुख्य वाहक थे। तथापि, ऋण वृद्धि की गति नवम्बर, 2018 से धीमी पड़ गई है। नवम्बर, 2018 में ऋण वृद्धि 13.8 प्रतिशत से घटकर अप्रैल, 2019 में 11.9 प्रतिशत पर आ गई। इस धीमी गति में मुख्य योगदान सेवा सेक्टर का रहा है जिसकी गति नवम्बर, 2018 और अप्रैल, 2019 के बीच 28.1 प्रतिशत से कम होकर 16.8 प्रतिशत पर आ गई। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को बैंक ऋण में वृद्धि अक्टूबर, 2018 से कम हो गई है।

कृषि

देश में कुल खाद्यानों का उत्पादन 2017-18 में 285 मिलियन टन अंतिम अनुमान की तुलना में 2018-19 में 283.4 मिलियन टन (तीसरा अग्रिम अनुमान) रहने का अनुमान है। 2018-19 के दौरान चावल का कुल उत्पादन रिकार्ड 115.6 मिलियन टन अनुमानित है। पिछले वर्ष के 112.8 मिलियन टन चावल के उत्पादन की अपेक्षा इसका उत्पादन 2.8 मिलियन टन बढ़ गया है। यह 107.8 मिलियन टन पांच वर्ष के औसत उत्पादन की अपेक्षा 7.8 मिलियन टन अधिक है। गेहूँ का उत्पादन रिकार्ड 101.2 मिलियन टन रहने का अनुमान है, जो 2017-18 के दौरान 99.9 मिलियन टन के उत्पादन की तुलना में 1.3 मिलियन टन अधिक है। इसके अलावा, 94.6 मिलियन टन पांच वर्ष के औसत गेहूँ उत्पादन की तुलना में 2018-19 के दौरान गेहूँ का उत्पादन 6.6 मिलियन टन अधिक है।

दुग्ध उत्पादन में भारत पहले नम्बर पर है, जो विश्व उत्पादन के 20 प्रतिशत का उत्पादन करता है। पिछले कुछ वर्षों में भारत में दूध का उत्पादन क्रमिक रूप से बढ़ता हुआ 4.5 प्रतिशत के औसत वार्षिक वृद्धि दर पर 1991-92 में 55.6 मिलियन टन से बढ़कर 2017-18 में 176.3 मिलियन टन हो गया है। वर्ष 2017-18 में 12.6 मिलियन मीट्रिक टन के कुल उत्पादन के साथ भारत विश्व में तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक है जिसमें से 65 प्रतिशत अंतर्देशीय क्षेत्र से आता था। अंतर्देशीय मछली उत्पादन का लगभग 50 प्रतिशत भाग मत्स्य पालन से होता है जो वैश्विक मछली उत्पादन का 6.5 प्रतिशत है। यह क्षेत्र कुल सकल मूल्य वर्धन में क्रमिक वृद्धि दर्ज कर रहा है और इसकी कृषि जीडीपी में 5.23 प्रतिशत की हिस्सेदारी है। मछली और मछली उत्पाद निर्यात 2017-18 में ₹45107 करोड़ के साथ मूल्य के संदर्भ में कृषि निर्यातों में सबसे बड़े समूह के रूप में उभर कर आया है।

2018-19 में कृषि ऋण प्रवाह लक्ष्य ₹11,00,000 करोड़ पर नियत किया गया था और इस लक्ष्य की तुलना में जैसा कि नाबार्ड द्वारा सूचित किया गया था, सितम्बर, 2018 तक बैंकों द्वारा ₹6,45,205 करोड़ वितरित किया गया।

उद्योग

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) के आधार औद्योगिक क्षेत्र जिसमें खनन, विनिर्माण और बिजली क्षेत्र शामिल है, के प्रदर्शन में 2017-18 में 4.4 प्रतिशत की तुलना में 2018-19 में 3.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। क्षेत्रीय वर्गीकरण के अनुसार 2018-19 के दौरान खनन, विनिर्माण और बिजली क्षेत्रों ने क्रमशः 2.9 प्रतिशत, 3.6 प्रतिशत और 5.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है। उपयोग आधारित वर्गों के बीच, प्राथमिक वस्तु, पूंजीगत वस्तु, मध्यवर्ती वस्तु, अवसंरचना/निर्माण संबंधी वस्तुओं, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं और उपभोक्ता गैर-टिकाऊ वस्तुओं

ने 2018-19 में क्रमशः 3.5 प्रतिशत, 2.8 प्रतिशत, (-) 0.5 प्रतिशत, 7.5 प्रतिशत, 5.5 प्रतिशत और 3.9 प्रतिशत की वृद्धि हासिल की है।

आठ प्रमुख अवसंरचना सहयोगी उद्योगों अर्थात कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और विद्युत जिनकी औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में लगभग 40 प्रतिशत की हिस्सेदारी है, 2017-18 में 4.3 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 2018-19 में भी इसी स्तर पर 4.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। 2018-19 के दौरान कोयला, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और विद्युत का उत्पादन क्रमशः 7.4 प्रतिशत, 0.8 प्रतिशत, 3.1 प्रतिशत, 0.3 प्रतिशत, 4.7 प्रतिशत, 13.3 प्रतिशत और 5.2 प्रतिशत बढ़ा जबकि इसी अवधि के दौरान कच्चे तेल का उत्पादन घट गया।

संभावनाएं

आशा है कि वर्ष 2019-20 में अर्थव्यवस्था की वृद्धि की गति सुदृढ़ होगी। वर्ष 2019-20 के भारतीय अर्थव्यवस्था की संभावनाओं का आकलन उभरते वैश्विक और घरेलू घटनाक्रमों के आलोक में किए जाने की आवश्यकता है। आशंका है कि 2019 में वैश्विक आर्थिक वृद्धि की गति मंद रहेगी जिससे भारत की निर्यात वृद्धि बाधित होगी तथापि, उम्मीद है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि रफ्तार पकड़ेगी। अर्थव्यवस्था में निवेश संबंधी गतिविधि में पुनरूद्धार के संकेत मिले हैं और नियत निवेश की वृद्धि में हालिया तेजी के आगामी वर्ष में बरकरार रहने की आशा की जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा भारत की वृद्धि को सुदृढ़ बनाने के लिए अनुमानों के अनुरूप वित्त वर्ष 2019-20 में अर्थव्यवस्था की 11.0 प्रतिशत अंकित वृद्धि होने का अनुमान है।

वृहत आर्थिक रूपरेखा विवरण
(आर्थिक निष्पादन : एक दृष्टि में)

क्र.सं.	मद	निरपेक्ष मूल्य अप्रैल-मार्च 2017-18	निरपेक्ष मूल्य अप्रैल-मार्च 2018-19	प्रतिशत परिवर्तन अप्रैल-मार्च 2017-18	प्रतिशत परिवर्तन अप्रैल-मार्च 2018-19
संपदा क्षेत्र					
1.	बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद (₹ हजार करोड़)@				
	(क) वर्तमान मूल्यों पर	17095	19010	11.3	11.2
	(ख) वर्ष 2011-2012 के मूल्यों पर	13180	14078	7.2	6.8
2.	औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक (2011-12=100)	125.3	129.8	4.4	3.6
3.	थोक मूल्य सूचकांक (2011-12=100)	114.9	119.8	3.0	4.3
4.	उपभोक्ता मूल्य सूचकांकः नई श्रृंखला (2012=100)	135.0	139.6	3.6	3.4
5.	मुद्रा आपूर्ति (एम3) (₹ हजार करोड़)	13962.6	15430.9	9.2	10.5
6.	वर्तमान मूल्यों पर आयात*				
	(क) ₹ करोड़	3001033	3587684	16.4	19.5
	(ख) मिलियन अमरीकी डालर	465581	513086	21.1	10.2
7.	वर्तमान मूल्यों पर निर्यात*				
	(क) ₹ करोड़	1956515	2303898	5.8	17.8
	(ख) मिलियन अमरीकी डालर	303526	329536	10.0	8.6
8.	व्यापार घाटा (मिलियन अमरीकी डालर)*	-162055	-183550	49.4	13.3
9.	विदेशी मुद्रा भंडार (मार्च अंत तक)				
	(क) ₹ करोड़	2760850	2855880	15.1	3.4
	(ख) मिलियन अमरीकी डालर	424545	412871	14.8	-2.7
10.	चालू खाता शेष (मिलियन अमरीकी डालर)#	-35651	-51865		
	सरकार के वित्त साधन (₹ करोड़)##				
1.	राजस्व प्राप्तियां	1435233	1563170	4.4	8.9
	सकल कर राजस्व	1919009	2080203	11.8	8.4
	कर (केन्द्र को निवल)	1242488	1316951	12.8	6.0
	कर-भिन्न राजस्व	192745	246219	-29.4	27.7
2.	पूंजी प्राप्तियां, जिसमें	706740	748252	17.6	5.9
	ऋणों की वसूली	15633	17840	-11.3	14.1
	अन्य प्राप्तियां	100045	85045	109.5	-15.0
	उधार और अन्य देनदारियां	591062	645367	10.4	9.2
3.	कुल प्राप्तियां (1+2)	2141973	2311422	8.4	7.9
4.	कुल व्यय	2141973	2311422	8.4	7.9
	(क) राजस्व व्यय	1878833	2008463	11.1	6.9
	जिसमें से पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान	191034	191220	15.3	0.1
	ब्याज भुगतान	528952	582675	10	10.1
	प्रमुख सब्सिडियां	191183	197066	-6.3	3.1
	पेंशन	145745	160123	10.9	9.9
	(ख) पूंजी व्यय	263140	302959	-7.5	15.1
5.	राजस्व घाटा	443600	445293	-	-
6.	प्रभावी राजस्व घाटा	252566	254073	-	-
7.	राजकोषीय घाटा	591062	645367	-	-
8.	प्राथमिक घाटा	62110	62692	-	-

@ *सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़े अप्रैल से मार्च तक के हैं और वर्ष 2018-19 के आंकड़े अनंतिम अनुमान हैं और वर्ष 2017-18 के आंकड़े प्रथम संशोधित अनुमान हैं।*

* *सीमाशुल्क आधार पर*

\# *अप्रैल - दिसंबर*

\## *1. महालेखा नियंत्रक और वित्त मंत्रालय द्वारा यथा सूचित अप्रैल-मार्च के आंकड़े।*
2. 2017-18 के आंकड़े अंतरिम बजट 2019-20 के वास्तविक आंकड़े हैं।